कक्षा - 12

स्वतंत्र भारत में राजनीति

अध्याय - 8

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

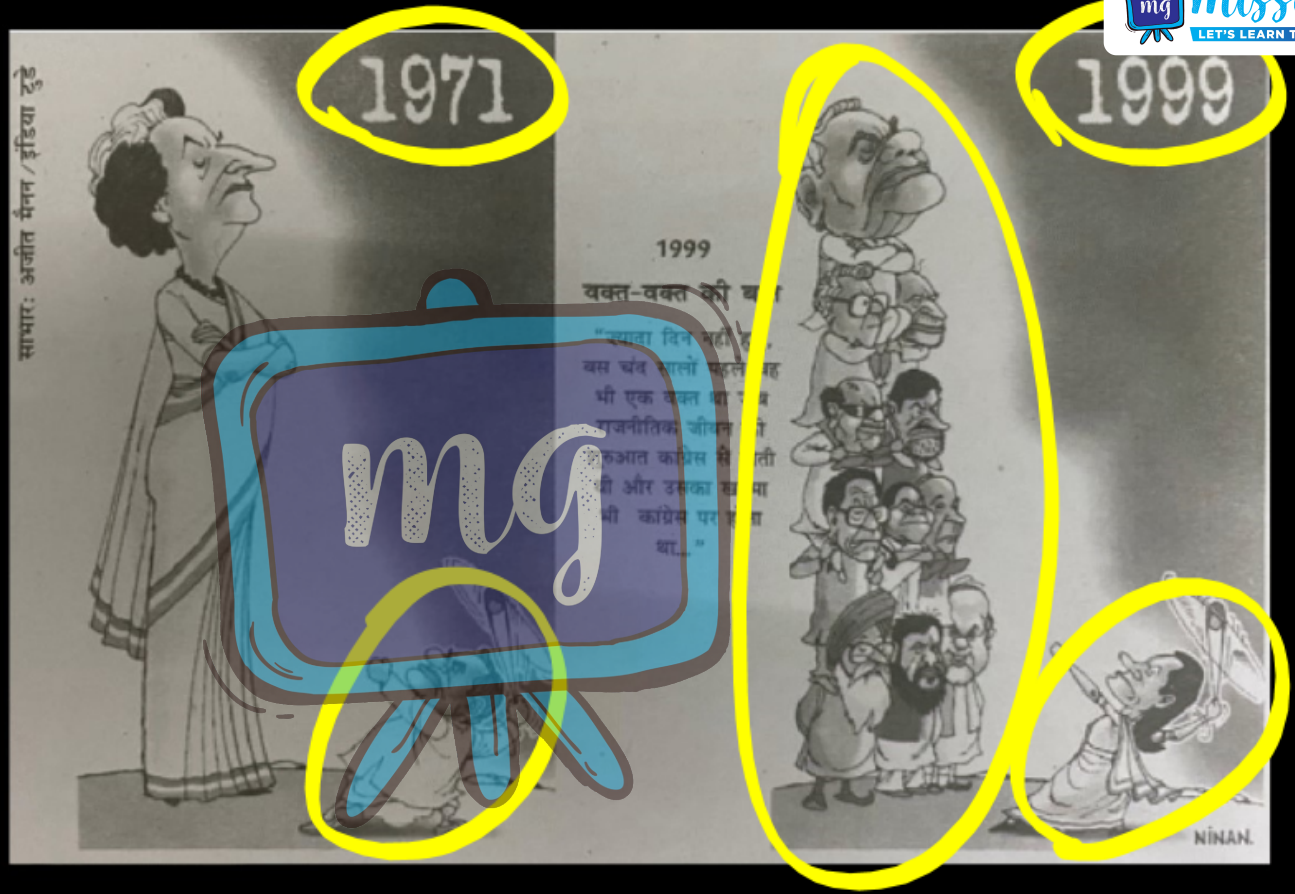
भाग - 2

Satyaveer Yadav

ipca
A dose of life

50%+

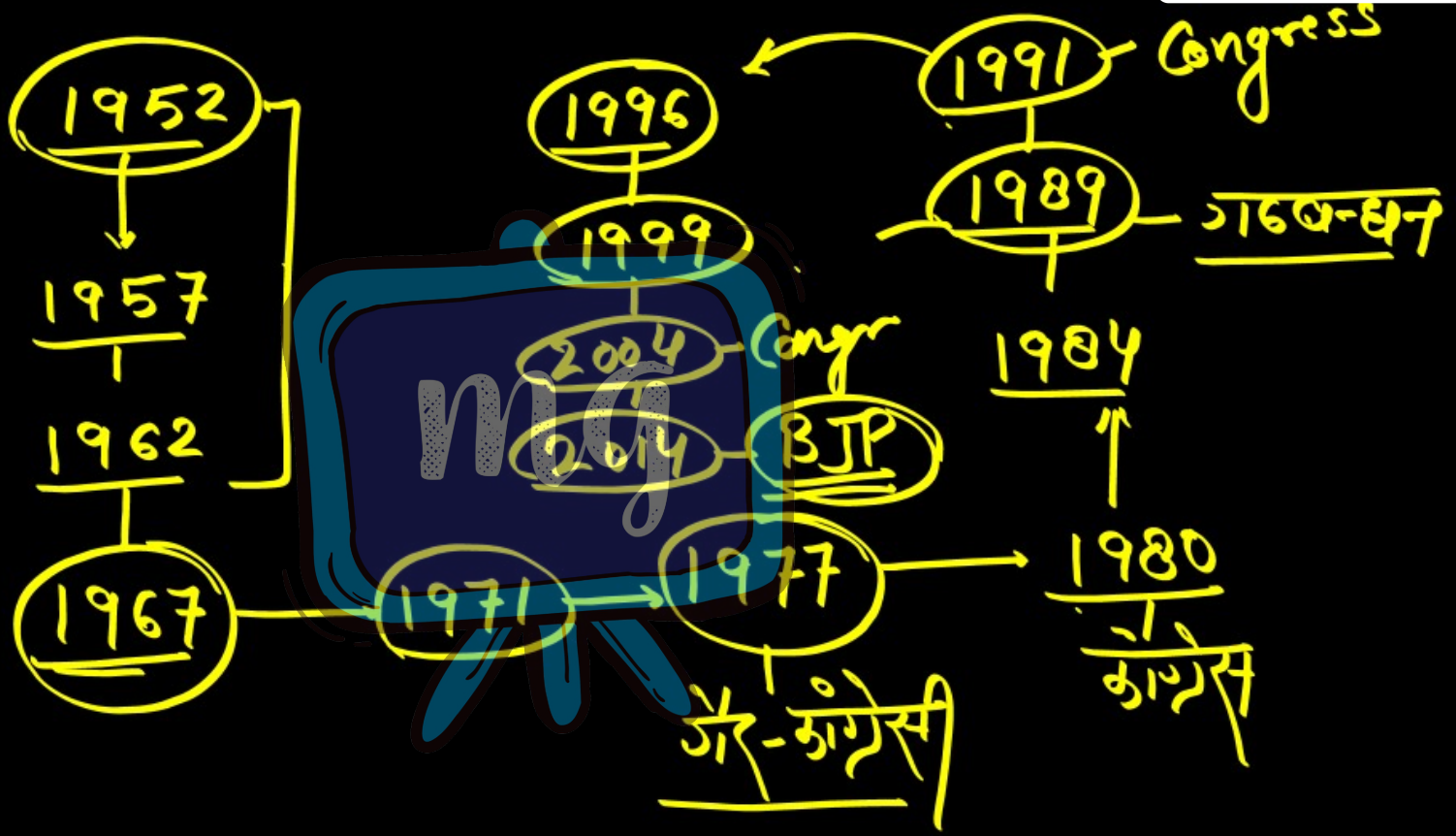
2/3+



mg missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

ipca
A dose of life

mg missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

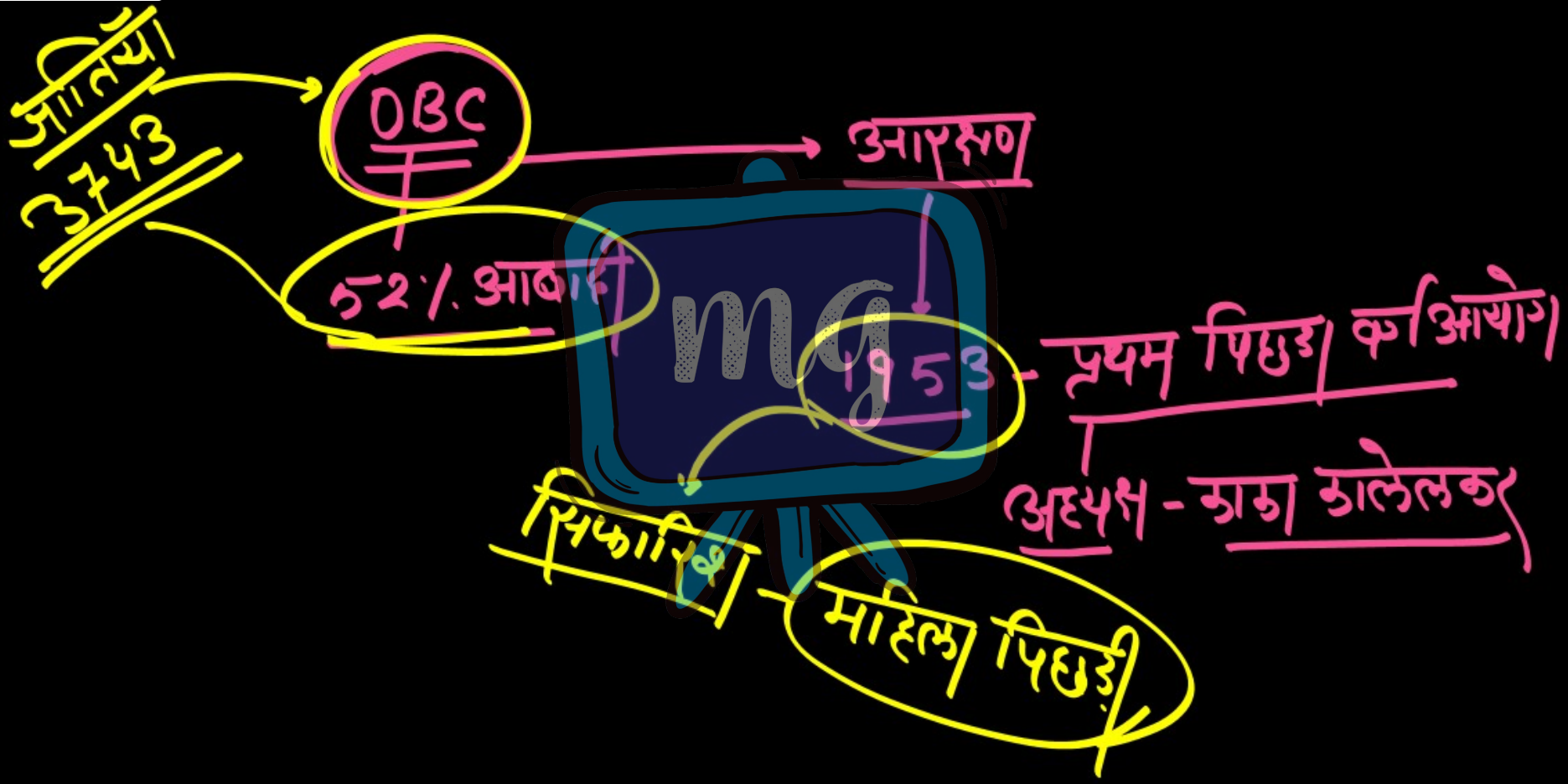


- 1989 के चुनावों से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरूआत।
- इसके बाद केन्द्र में 11 सरकारें बनीं।
- ये सभी या तो गठबंधन की सरकारें थी अथवा दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत की सरकारें थीं।
- यह बात 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1996 और 1997 की संयुक्त मोर्चा सरकार, 1998 और 1999 की राजग, 2004 और 2009 की सप्रंग सरकार समान रूप से लागू होती है।
- हालांकि यह प्रवृत्ति 2014 में बदल गयी।

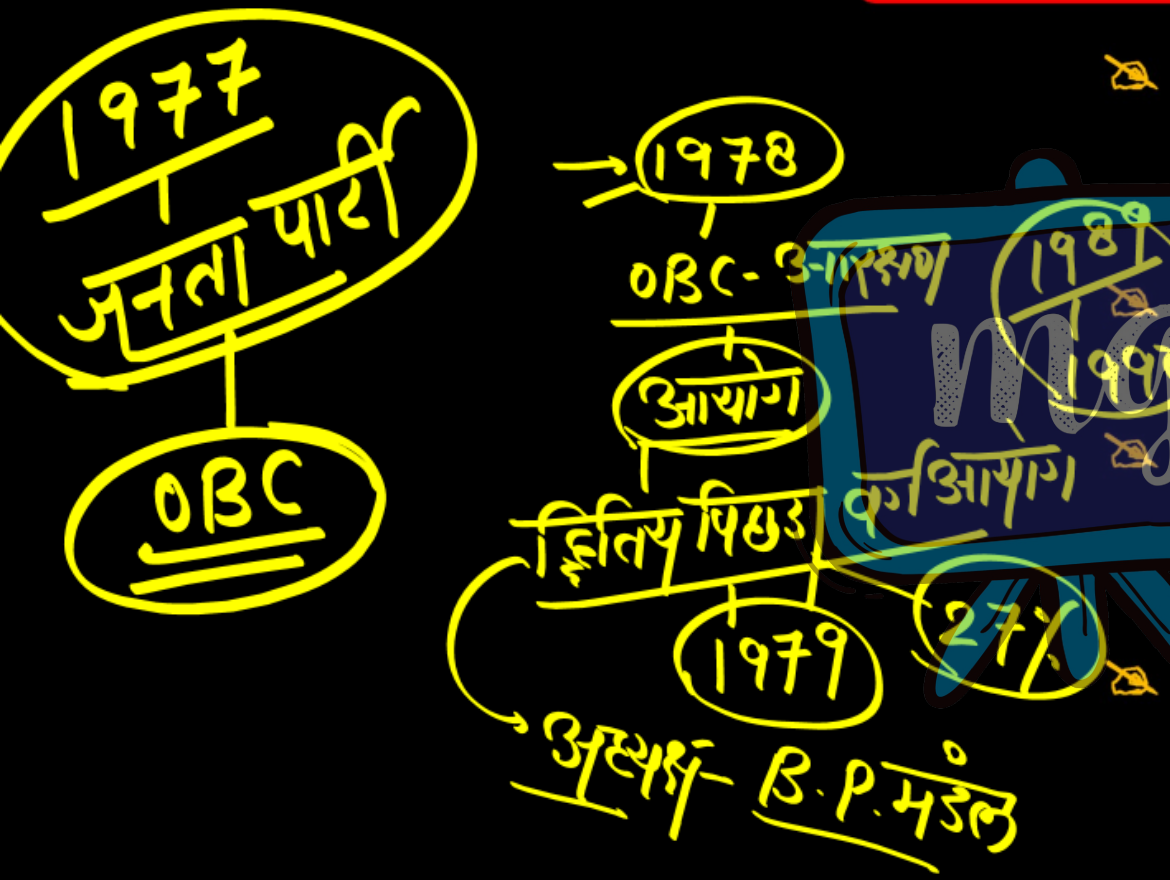

अन्य पिछड़ा वर्ग
OBC
SC, ST से अलग एक कोटा है, जिसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की गणना की जाती है।
इन्हें पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है।
पिछड़ी जातियों के तबके कांग्रेस से दूर जा रहे थे।
गैर–कांग्रेसी दलों ने इनका समर्थन हासिल किया।

ipca
A dose of life

mg missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER



मंडल का लागू होना



1980 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच लोकप्रिय ऐसे ही राजनीतिक समूहों को जनता दल ने एकजुट किया।

राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया।

नौकरी में आरक्षण के सवाल पर तीखे वाद-विवाद हुए और इन विवादों से अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज्यादा सजग हुआ।

इस दौर में ऐसी अनेक जातियाँ आगे आयीं, जिन्होंने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की मांग की।

ipca
A dose of life

mg missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

इन दलों का कहना था कि भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसे देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का शासन में समुचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में समुचित मौजूदगी तय करना लोकतांत्रिक कदम होगा।



ipca
A dose of life

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

मंडल आयोग

मोरार जी

- 1977 - 79 की जनता पार्टी की सरकार के समय उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से आवाज उठायी गयी।
- बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इस दिशा में अग्रणी थे।
- उनकी सरकार ने बिहार में 'ओबीसी' को आरक्षण देने के लिए एक नयी नीति लागू की।
- इसके बाद केन्द्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बैठाया।
- इसके जिम्मे पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारने का उपाय बताने का काम सौंपा गया था।

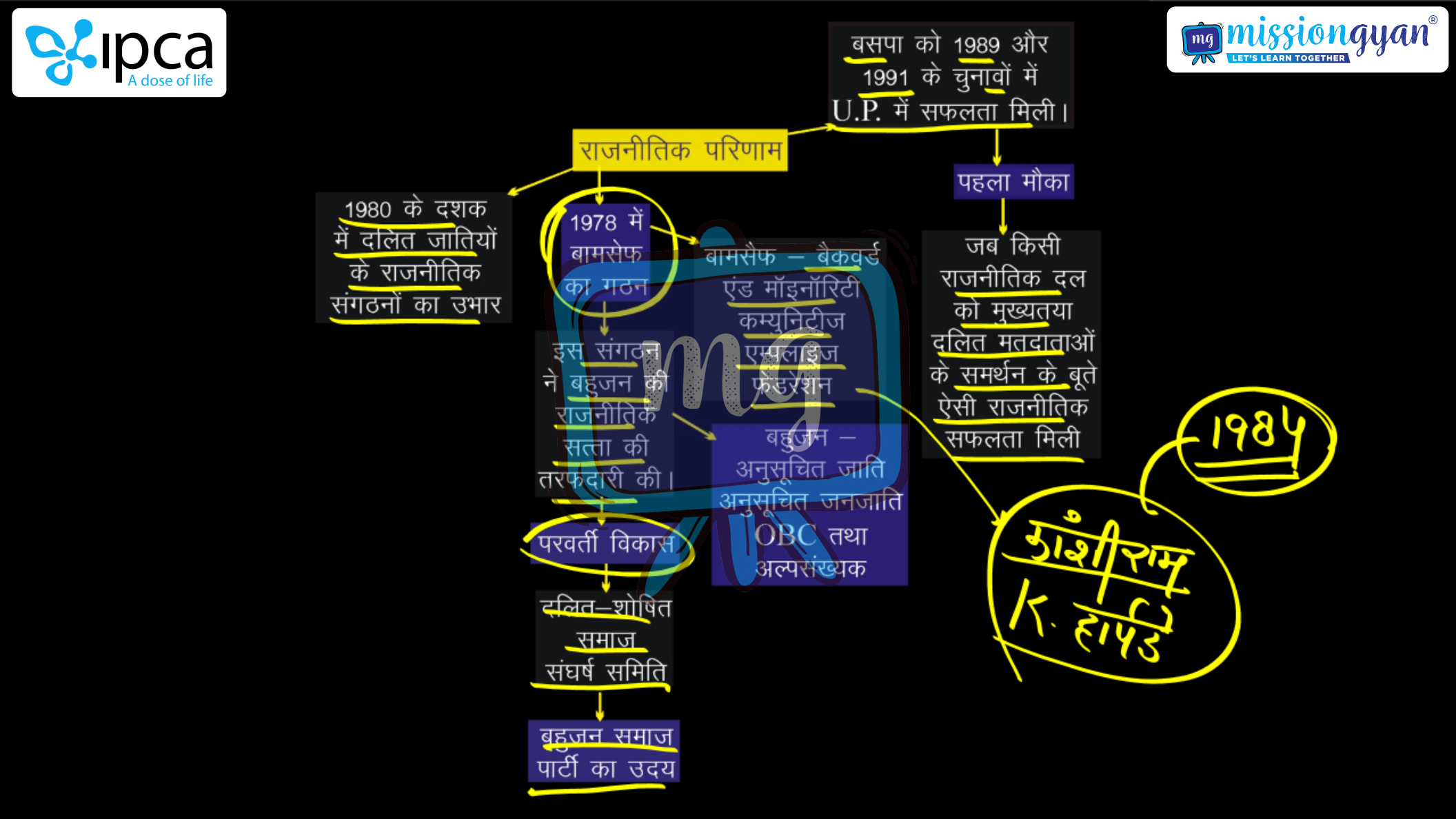
इस आयोग के अध्यक्ष बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल थे, उनके नाम इसे 'मंडल आयोग' कहा जाता है।

ipca
A dose of life

सिफारिशें

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

- आयोग का मशविरा था कि पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाये, क्योंकि अनुसूचित जातियों से इतर ऐसी अनेक जातियां है, जिन्हें वर्ण व्यवस्था में 'नीच' समझा जाता है।
- आयोग ने सर्वेक्षण में पाया कि इन पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी हैं।
- इस वजह से आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत सीट आरक्षित करने की सिफारिश की।
- मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई और समाधान सुझाये जिनमें भूमि-सुधार भी एक था।


बसपा को 1989 और 1991 के चुनावों में U.P. में सफलता मिली।
राजनीतिक परिणाम
1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का उभार
1978 में बामसेफ का गठन
बामसैफ – बैकवर्ड एंड मॉइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्पलाइज फेडरेशन
इस संगठन ने बहुजन की राजनीतिक सत्ता की तरफदारी की।
बहुजन – अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति OBC तथा अल्पसंख्यक
परवर्ती विकास
दलित–शोषित समाज संघर्ष समिति
बहुजन समाज पार्टी का उदय
पहला मौका
जब किसी राजनीतिक दल को मुख्यतया दलित मतदाताओं के समर्थन के बूते ऐसी राजनीतिक सफलता मिली
1984
कांशीराम
R. हार्ड